

## शपि एकवीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग: IFSCA रपिर्ट

### प्रलिमिंस के लयि:

अंतर्राष्ट्रीय वत्तीय सेवा केंद्र प्राधकिरण, शपि एकवीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग

### मेन्स के लयि:

भारत के लयि नौवहन क्षेत्र का महत्त्व

### चर्चा में क्यों?

हाल ही में 'जहाज़ अधगिरहण, वत्तिपोषण और पट्टे हेतु एवेन्यू के विकास के लयि गठति समति द्विवा 'अंतर्राष्ट्रीय वत्तीय सेवा केंद्र प्राधकिरण' (IFSCA) को 'शपि एकवीज़ीशन, फाइनेंसिंग एंड लीज़िंग (SAFAL) शीर्षक से एक रपिर्ट प्रस्तुत की गई है।

### प्रमुख बदि

#### ■ समति के वषिय में:

- **गठन:** इसका गठन IFSCA द्वारा जून 2021 में भारत सरकार, गुजरात मैरीटाइम बोर्ड, उद्योग और वत्ति वशिषज्जों तथा शकिषावदिों के प्रतनिधियों के साथ कयि गया था।
- **उद्देश्य:** यह मुख्य तौर पर IFSC से स्वामतिव और पट्टे पर लयि गए जहाज़ों की शपिगि सेवाओं के लागत प्रभावी और प्रतसिपर्द्धी डलिीवरी को सक्षम करने और उन्हें वदिशी प्रतसिपर्द्धियों के बराबर लाने पर फोकस करता है।

#### ■ समति के नषिकर्ष:

- **शपिगि सेवाओं का शुद्ध आयातक:** एक व्यापक तटरेखा, बढ़ते घरेलू बाज़ार और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार, प्राचीन समुद्री परंपराओं तथा कुशल नावकों के बावजूद अंतर्राष्ट्रीय शपिगि क्षेत्र में भारत का हसिंसा काफी कम है, इस प्रकार यह शपिगि का शुद्ध आयातक बन गया है।
- **आवश्यक परविरतन:** इसने ग्रीनफील्ड उद्यम को IFSC के दायरे में लाने के लयि महत्त्वपूर्ण एवं आवश्यक परविरतन कयि हैं।
  - इनमें कानूनी एवं नयामक डोमेन, प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर और वैश्वकि सर्वोत्तम प्रथाओं पर आधारति 'व्यापार सुगमता' शामिल है।
- **ब्रांड वैल्यू प्रदान करना: यह भारतीय ध्वज वाले जहाज़ों को ब्रांड वैल्यू प्रदान करने का उपयुक्त समय है।**
  - यह लक्ष्य वैश्वकि क्रॉस टरेडों में हसिंसेदार बनाकर, भारत के बाज़ार के लयि लाभकारी लेन-देन हासलि कर नीले महासागरों में डीकारबोनाइज़ेशन एवं हरयिली को बढ़ावा देने और मैरीटाइम इंडयिा वज़िन 2030 तथा उससे आगे के लयि भारत-आईएफएससी मैरीटाइम का लाभ उठाकर प्राप्त कयि जा सकता है।
    - मैरीटाइम इंडयिा वज़िन 2030 समुद्री क्षेत्र के लयि दस वर्ष का ब्लूपरटि है, जसि नवंबर 2020 में मैरीटाइम इंडयिा समटि में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा जारी कयि गया था।
    - यह 'सागरमाला पहल' का स्थान लेगा और इसका उद्देश्य जलमार्ग को बढ़ावा देना, जहाज़ नरिमाण उद्योग के वसितार तथा भारत में करूज़ पर्यटन को प्रोत्साहति करना है।

#### ■ भारत के लयि नौवहन क्षेत्र का महत्त्व:

- भारत की लगभग आधी सीमा समुद्र से घरि हुई है और देश की तटरेखा लगभग 7,517 कलिमीटर है, जसिमें 12 बड़े और 205 छोटे बंदरगाह शामिल हैं।
  - भारत रणनीतिक रूप से दुनयिा के नौवहन मार्गों पर स्थति है।
- यह अनुमान है कि भारत का लगभग 95% माल का व्यापार मात्रा के हसिाब से और 70% मूल्य के हसिाब से समुद्री परविहन के माध्यम से कयि जाता है।
- समुद्री माल भाड़ा दर में भी भारत महत्त्वपूर्ण जोखमि का सामना कर रहा है। भारत में समुद्री माल ढुलाई प्रतविर्ष 85 अरब डॉलर अनुमानति है।
  - वत्तीय वर्ष 2019-20 में भारत के नरियात-आयात कार्गो को ले जाने में भारतीय जहाज़ों की हसिंसेदारी लगभग 6.53% थी।
  - अनुमान है कि भारत प्रतविर्ष वदिशी शपिगि कंपनयिों को लगभग 75 बलियिन डॉलर समुद्री माल का भुगतान करता है।

• इस प्रकार भारत शपिगि उद्योग में अपने नविश को बढ़ाने के लिये बेहतर स्थिति में है ।

■ **सरकार द्वारा किये गए संबंधित उपाय:**

- **पहले इनकार के अधिकार (ROFR) के मानदंडों में संशोधन:** भारत में भारतीय ध्वजांकित और जहाज़ निर्माण के तहत टन भार को बढ़ावा देने के लिये नविदि प्रक्रिया के माध्यम से जहाज़ों को करिए पर लेने में **पहले इनकार का अधिकार** देने के मानदंड को संशोधित किया गया है, ताकि भारत में टन भार और जहाज़ निर्माण के मामले में भारत को **आत्मनिर्भर** बनाया जा सके ।
- **भारतीय नौवहन कंपनियों को सबसिडी सहायता:** मंत्रालयों और CPSE द्वारा जारी वैश्विक नविदाओं में भारतीय शपिगि कंपनियों को सबसिडी सहायता के रूप में पाँच वर्ष की अवधि में 1,624 करोड़ रुपए प्रदान करके भारतीय ध्वजांकित व्यापारिक जहाज़ों को बढ़ावा देने के लिये एक योजना को कैबिनेट द्वारा अनुमोदित किया गया है ।
- **जहाज़ निर्माण वित्तीय सहायता नीति (2016-2026):** भारत सरकार ने भारतीय शपियार्डों को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु दिसंबर 2015 में भारतीय शपियार्ड के लिये वित्तीय सहायता नीति को मंजूरी दी ।

## अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (IFSC):

- IFSC उन वित्तीय सेवाओं और नविश को भारत में वापस लाने में सक्षम बनाते हैं जो वर्तमान में भारतीय कॉर्पोरेट संस्थाओं और वदेशी शाखाओं/वित्तीय संस्थानों की सहायक कंपनियों (जैसे बैंक, बीमा कंपनियों आदि) द्वारा भारत के अपतटीय वित्तीय केंद्रों में किये जाते हैं ।
  - ये केंद्र व्यावसायिक और वनियामक स्थिति प्रदान कर प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान की तुलना में विश्व के अन्य वित्तीय केंद्रों जैसे- लंदन और सगिापुर में किये जाते हैं ।
- IFSC का उद्देश्य **भारतीय कॉर्पोरेट्स को वैश्विक वित्तीय बाज़ारों तक आसान पहुँच प्रदान करना** और भारत में वित्तीय बाज़ारों के विकास को बढ़ावा देना है ।
- भारत में पहला IFSC गांधीनगर में **गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (GIFT City)** में स्थापित किया गया है ।
- केंद्र सरकार ने गांधीनगर (गुजरात) में मुख्यालय के साथ अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों (IFSCs) में सभी वित्तीय सेवाओं को वनियमित करने के लिये **अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण** की स्थापना की है ।

स्रोत: पीआईबी

PDF Refernece URL: <https://www.drishtiiias.com/hindi/printpdf/ship-acquisition,-financing-and-leasing-safal-ifsc-report>

